भारतीय जनता पार्टी

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700; **फैक्स :** 23005787

दिनांक : 28 फरवरी 2013

लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा दिया गया वक्तव्य

संसद में आज पेश केन्द्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रतिकूल परिस्थितियों में बजट पेश किया। यूपीए अपनी विवेकशून्य नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को खराब स्थिति में पहुंचा चुकी है। वित्त मंत्री खुद को असहाय स्थिति में पा रहे थे जिसमें बहुत कम गुंजायश थी। इसलिए उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिसमें नीतिगत और कराधान ढांचे में कुछ दिखावटी बदलाव किये गए। हांलाकि बजट शब्दों का मकड़जाल था, लेकिन इसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी। इसमें भारतीय निर्माण क्षेत्र के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने लगातार कृषि की अनदेखी की है। यहां तक की आम आदमी का जिक्र करने की रस्म भी पूरी नहीं की गई। इसमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए जिनसे निर्यात को बढ़ावा मिले, मुद्रास्फीति पर अंकुश लग सके और रुपया मजबूत हो सके। अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी विकास दर को 5 प्रतिशत पर लाकर यूपीए अपने नवीनतम बजट में 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लक्ष्य तक वापस पहुंचने के लिए आरंभिक रोडमैप पेश करने में विफल रही है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कुछ वर्गों के लिए कर की दरों को बढ़ाने घटाने में बाजीगरी करके खर्च में कटौती की गई है। खर्च में कटौती करके इस वर्ष और अगले वर्ष के वित्तीय घाटे को बेहतर प्रदर्शित किया गया है। विस्तृत बजट दस्तावेज में इसके कई उदाहरण है। इस वर्ष के खाद्य सब्सिडी विधेयक में 75,000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया था। वास्तविक संशोधित अनुमान का खर्च 85,000 करोड़ रुपये है। अगले वर्ष के बजट अनुमानों में यह राशि घटाकर 80,000 करोड़ रुपये कर दी गई है और वित्त मंत्री का दावा है कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा विधेयक के कारण 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वास्तव में यह केवल 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि है जिसमें जिसका खाद्य सब्सिडी पर

मामूली असर होगा। स्वास्थ्य मिशन पर वर्तमान वर्ष के बजट में 18515 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, संशोधित अनुमान 15411 करोड़ रुपये है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में मामूली बढ़ोतरी करके यह राशि 3000 करोड़ रुपये हो जाती है। पंचायती राज के खर्च के संबंध में भी यही स्थिति है। यूपीए की प्रमुख योजना मनरेगा के लिए मूल रुप से 40,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। पिछले दो वर्षों के दौरान यह राशि घटाकर 33,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। वर्तमान वर्ष का वास्तविक अनुमान 29387 करोड़ रुपये है। अगले वर्ष वास्तविक खर्च इससे भी कम हो सकता है। वित्त मंत्री ने पूरी तरह यह जानते हुए कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इसे पुराने प्रस्तावित लक्ष्य 33,000 करोड़ रुपये पर ले आए हैं। विफलता का स्पष्ट प्रमाण प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 29677 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 40 प्रतिशत कमी के साथ 8100 करोड़ रुपये है।

यूपीए अपने नये कार्यक्रम प्रत्यक्ष नगदी लाभ हस्तांतरण योजना की बहुम शेखी बघार रहा है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी 26 योजनाओं के लिए बजट में 5595.02 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। अभी तक वास्तविक खर्च केवल 5.38 करोड़ रुपये हुआ है। यह कहा गया था कि इस योजना से भारतीय राजनीति की दिशा बदल जाएगी।

बजट में एक चेतावनी है। 96980 करोड़ रुपये की पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें और बढ़ जाएंगी।

बजट नीति संबंधी वक्तव्य नहीं है। इसमें कोई नई दिशा नहीं दिखाई गई है। यह केवल एक हिसाब–किताब की कवायद है जिसमें खर्च की कटौती की गई है और बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। इससे विकास दर नहीं बढ़ेगी। गरीब और कमजोर वर्ग के साथ मध्यम वर्ग बुरी तरह पिसेगा।

आर. के. सिन्हा
सचिव
भाजपा संसदीय दल